Golden Research thoughts
Volume 2, Issue. 1, July 2012
ISSN:-2231-5063

Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास सहकारी बैंक की दशा व दिशा

***हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा*[1], *रवीश कुमार सोनी*[2],*भुनेश्वर प्रसाद*[3]**

[1]प्रिंसीपल इंवेस्टिगेटर, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट (यू.जी.सी)प्राध्यापक –वाणिज्य शास.वि.ना.या.ता.महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)
[2]सहा. प्राध्यापक–वाणिज्यकल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई दुर्ग (छ.ग.)
[3]प्रोजेक्ट फेलो, मेंजर रिसर्च प्रोजेक्ट (यू.जी.सी.)
soni.ravish27@gmail.com

प्रस्तावना :–

भारत गाँवों का देश है यहाँ की 70: आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश की 64: कार्यशील जनसंख्या को रोजगार प्राप्त है एवं घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 26.5: है। भारत की ग्रामीण जनता की जीविका का आधार मुख्यतः कृषि है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही हमारे राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों की केन्द्रीय धुरी है। यदि हम राष्ट्र व प्रदेश के विकास एवं आत्मनिर्भरता की कल्पना करते है तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान कृशि एवं कृषि वित्त पर केन्द्रीत होता है। छततीसगढ राज्य की सबसे अधिक श्रम शक्ति कृषि व कृषि सहायक कार्यों के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रही है। यह शक्ति अनादिकाल से लोक प्रिय रही है और आज भी यह अटल सत्य है। कृषि विकास के अभाव में आर्थिक उन्नयन की योजनाएँ दिवास्वप्न ही सिद्ध होगी ।

स्वतंत्रता पूर्व से कृषक सामान्यतः सहकारों पर ऋण (कृषि वित्त) हेतु निर्भर रहते थे। साहूकार शीघ्रता से उत्पादन एवं अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण तो देते थे, किन्तु ऊँची व्याज दरों पर ऋण लेकर उनका शोषण करते थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक बैंक की बहुत कम शाखायें हैं एवं अत्याधिक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद भी ये बैंक कृषि के लिए बहुत कम ऋण उपलब्ध करते हैं।

छत्तीसगढ़ में समन्वयवादी संस्कृति एवं सबको साथ लेकर चलने को ऐतिहासिक परम्परा से जन्मा है सहकारी क्षेत्र। कृषि साख की कमी एवं व्यवसायिक बैंकों से कृषि के प्रति उदासीनता के परिणामस्वरूप सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पूर्व नाम भूमि विकास बैंक) अस्तित्व में आये।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के केन्द्र बिन्दु कृषि क्षेत्र की प्रारंभिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाओं की उपलब्धि एक अपरिहार्य दशा है, वर्तमान परिस्थितियों में बैंकिंग ग्रामीण समाज की परम्परागत संरचना को रूपान्तरित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को व्यवहार्य बनाने का एक प्रभावी माध्यम माना गया है। गतिहीन साख को गतिशील साख में परिवर्तित करने के दर्शन के अन्तर्गत संस्थागत साख की भूमिका सर्वविदित है। अधिकांश देशों मे किसानों को साख सुविधायें प्रदान करने में सहकारी बैंकिंग को सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया है, चाहे उसका मूल कारण सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण साख की दशाओं का उचित अनुमान लगाना ही रहा हो। कृषि साख के चार मूलभूत सिद्धांतों–निकटता, जमानत, उत्पादकता तथा सुरक्षा के व्यापक ढांचे में कृषि के लिये साख की व्यवस्था करने का एक अस्त्र सहकारी बैंकिंग ही है।

छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लोकतांत्रिक संस्थायें होने के कारण छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी संलग्नता और सहभागिता से व्यापक रूप से समाये हुये हैं।

यह बैंक दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना का शीर्शस्थ बैंक है। प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि/अकृषि साख आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करना एवं बैंक से सम्बद्ध जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना इसका उत्तरदायित्व है।

किसी भी सहकारी साख संस्था की सक्षमता उसके द्वारा वितरित ऋण की वसूली पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की मांग वसूली की स्थिति राज्य गठन पश्चात् वर्ष 2009.10 तक निम्नानुसार है –

Please cite this Article as : *हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा*[1], *रवीश कुमार सोनी*[2],*भुनेश्वर प्रसाद*[3] ,*छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास सहकारी बैंक की दशा व दिशा* : **Golden Research Thoughts (July; 2012)**

सारिणी क्रमांक–1

क्र.	वर्ष	जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की मांग वसूली			छत्तीसगढ़ कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की मांग वसूली		
		मांग	वसूली	:	मांग	व्सूली	:
1.	2004.05	6976.79	4215.56	60.42	8585.74	3304.35	38.49
2.	2005.06	9653.45	4726.20	48.96	10252.85	3983.97	38.86
3.	2006.07	10326.11	5435.85	52.64	11542.36	4661.14	40.38
4.	2007.08	10955.60	5235.78	47.79	11627.80	2922.83	25.14
5.	2008.09	10680.71	5320.82	49.82	13261.92	5039.81	38.00
6.	2009.10	10943.07	5784.33	52.86	12777.73	4645.3	36.35

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन, छ.ग. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर

सरिणी –2

वर्शवार राज्य विकास बैंक की मांग वसूली का विवरण –

क्रमांक		मंग	वसूली	(राशि रू. लाखें में) प्रतिषत
1.	2001-01	1786.27	644.31	36.07%
2.	2001-02	3914-42	2086.41	53.30%
3.	2002-03	3567.23	1110.64	31.13%
4.	2003-04	7112.04	3184.42	44.78%
5.	2004-05	8585.74	3304.35	38.49%
6.	2005-06	10252.85	3983.97	38.86%
7.	2006-07	11542.36	4661.14	40.38%
8.	2007-08	11627.8	2922.83	25.14%
9.	2008-09	13261.92	5039.81	38.00%
10.	2009-10	12777.73	4645.3	36.35%

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन, छ.ग. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर

उपर्युक्त सारिणी को निम्न रूप में भी दर्शाया जा सकता है।

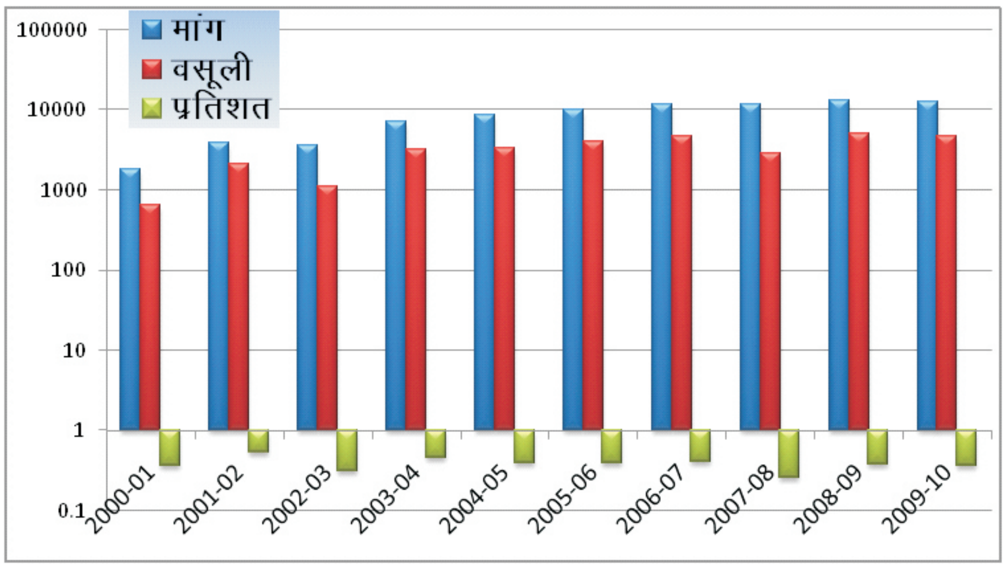

उपरोक्त सारिणी–2 में वर्षवार राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की मांग वसूली का विवरण का अवलोकन किया जा सकता है, जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा दिये गयें ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति राज्य विकास बैंक, निर्गमित ऋण पत्रों की राशि से करता है। ऋण पत्रों के सामयिक भुगतान के लिये राज्य विकास बैंक को राशि जिला विकास बैंकों द्वारा वसूली की राशि के सम्प्रेशण से प्राप्त होता है।

जिला विकास बैंकों के द्वारा वर्ष 2004.05 में 60.4ः वसूली कर राज्य विकास बैंक की मांग का 38.49ः भुगतान किया। वर्ष 2005.06 में राज्य विकास बैंक की मांग का 38.86ः भुगतान किया गया। इसी तरह से वर्ष 2006.07, 07.08, 08.09 तथा 2009.10 में राज्य राज्य विकास बैंक की मांग का 40.38ः, 24.14ः, 38.00ः तथा 36.35ः भुगतान किया गया। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है क जिला विकास बैंक उपलब्ध व्याज मार्जिन से स्पष्ट होता है कि अधिक राशि व्यवस्थापिकीय व्यय में खर्च कर रहा है। यह प्रवृत्ति बैंक की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से आगे प्रभावित करेगी।

किसी भी सहकारी साख संरचना की सक्षमता उनके द्वारा वितरित ऋण की वसूली पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। राज्य के जिला विकास बैंकों को औसत वसूली, वर्शं 2009.10 में 52.86ः रही है। जबकि ऋण वसूली का न्यूनतम राष्ट्रीय मापदण्ड 70ः है। प्रदेश के किसी भी जिला विकास बैंक के द्वारा 70ः है। वसूली नहीं की गई है और अधिकांश जिला विकास बैंकों ने राज्य विकास बैंक के मांग के विरूद्ध वसूली राशि पासआन करने में चूक किया है परिणामस्वरूप राज्य विकास बैंक की ऋण वसूली कम होने से राज्य विकास बैंक का NPA (Non Performing assets) 49.60ः हो गया हैजो राष्ट्रीय मापदण्ड 5ः से अधिक है।

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंकिग की चुनौतियाँ :–

सहकारी बैंकिंग अतिदेय ऋण तथा निम्न परिचालनगत व कार्यकुशलता से ग्रस्त हैं। इसके विपरीप वाणिज्यिक बैंकिंग ने इससे प्रतिस्पर्धा करके साख वितरण एवं वसूली में कहीं बेहतर निश्पादन किया है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेशण से विदित होता है कि कृषकों का व्यवहार ऋण चुकाने के मामले में उदासीन हो रहा है। इसके प्रमुख कारण–सहकारिताओं की दोषपूर्ण ऋण देने की नीति, अनुशासनाहीन सदस्यों पर तत्काल कार्यवाही करने से बचना, प्रबंधकों की उदासीनता तथा राज्य सरकारों की प्रवृत्ति के कारण अनुकूल वातावरण का अभाव जिसके परिणामस्वरूप काफी अधिक संख्या में ऋणकर्ता जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते। इस भारी अतिदेय की राशि के कारण ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये ऋण के पुनर्निवेशन में रूकावट आई है, जिससे ऋण की उपलब्धता तथा निविश्टियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता ।

सहकारी ऋण का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और आय को बढ़ाना है। लेकिन मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली से उत्पादन/उत्पादकता तथा ऋण के मध्य किसी सम्बद्धता का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी ऋण में तो भारी वृद्धि हुई है। पर उससे उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई। कृषि क्षेत्र में ऋण और उत्पादन के बीच संबद्ध ऋण के संस्थागत प्रवाह को उपयुक्त मार्ग पर लाने के अत्यधिक प्रयासों के बावजूद विरल होता जा रहा है, चाहे ऐसा मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्ति पर दिये जाने वाले प्रतिबल के कारण ही क्यो न हुआ हो।

सहकारिताओं के सम्मुख संगठनात्मक कुशलता के अभाव और प्रबंधकीय अपर्याप्तता की समस्या के कारण कृषि एवं ग्रामीण विकास संतुलित तरीके से नहीं हो पा रहा है।

उपचारात्मक उपाय :–

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु ऋण जमा संग्रहण पर बल देना होगा। हरितक्रांति के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में आय बड़ी है। अतः इस वृद्धिशील आमदनी के कुछ भाग का एकत्रित करना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में सहकारी बैंक जिनकी ग्रामीण जीवन में गहरी पैंठ है, इस कार्य को करने के लिये सर्वोत्म ऐजेन्सी है।

ग्रामीण क्षेत्र में निवेश तथा ग्रामीण समुदाय में बैंकिग आदतों के विकास को बहुत सारे कारण प्रभावित करते हैं जिससे अन्ततः बैंकिंग की लाभदायकता कम होती है। अतः सहकारी बैंकों को इस संबंध में अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे।

सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख को उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए। इसका अंतिम लक्ष्य कृशकों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाना होना चाहिए।

किसानों के बीच सहकारी बेंकिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रियायती दर पर अनेक सुविधायें देनी चाहिए।

सहकारी बैंक में सफल ऋण प्रणाली अपनाने के साथ–साथ स्थानीय सस्थाओ व निकायों की धनराशि को आकर्षित करने की महती आवश्यकता है राज्य सहकारी संघों को सहकारी प्रशिक्षण का कार्य अपना लेना चाहियें समितियों को अपने लाभों का कुछ भाग सहकारी शिक्षा कोश के लिये निर्धारित करना चाहिए। जिसमें ग्रामीण विकास के साथ बैंक की स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ :–

1.भारतीय अर्थशास्त्र – मिश्र एवं पुरी, हिमालयन पब्लिकेशन
2.भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. रीता माथुर
3.भारतीय बैंकिग की आधुनिक प्रवृत्तियों – सुबह सिंह यादव
4-www.cg.govt.in
5.वार्षिक प्रतिवेदन 2000.05 से 2009.10 छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर
6.व्यवसायिक वित्त – डॉ विवेक शर्मा